

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी- श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या- 53/2014

बउनवान

सरकार जयें तहसीलदार, मांगरोल जिला-बारां (राज०)

(प्रार्थी)

बनाम

1. इल्लामुद्दीन पुत्र कयामुद्दीन जाति मुसलमान,
2. कमलाबाई पत्नि रामचन्द्र, जाति गुर्जर, निवासीगण मांगरोल जिला बारां (राज०)

(अप्रार्थीगण)



रेफरेंस प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :- 1. परोकार सरकार

(प्रार्थी)

2. श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक

(अप्रार्थी क्र.सं. 1)

3. श्री हरीश राजावत अभिभाषक

(अप्रार्थी क्र.सं. 2)

आदेश दिनांक- 28.10.2022

1- प्रार्थी सरकार जयें तहसीलदार, मांगरोल ने रेफरेंस प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध अप्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम मांगरोल में जमाबंदी सम्वत् 2069-72 आराजी खसरा नंबर 645 रकबा 0.45 है., किस्म किस्म नहरी 1 अप्रार्थी क्रम का हिस्सा 1/7 व अप्रार्थी क्रम 2 का हिस्सा 6/7 खाते दर्ज है। आराजी खसरा नंबर 645 रकबा 0.45 है. मुताबिक मिलान क्षेत्रफल संवत् 2044-63 ग्राम मांगरोल के साबिक खसरा नंबर 701 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा से कायम हुए हैं। मुताबिक सेटलमेन्ट जमाबन्दी सम्वत् 2044-63 के अनुसार ग्राम मांगरोल में साबिक खसरा नं. 701 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा किस्म गै०मु० तलाई दर्ज रिकार्ड है। दौराने सेटलमेन्ट कार्य बन्दोबस्त कर्मचारियों ने आराजी साबिक खसरा नंबर 701 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा किस्म गै. मु. तलाई के हाल खसरा नंबर 645 रकबा 0.45 है., नहरी 1 कायम किये जाकर अवैधानिक रूप से अप्रार्थी क्रम 1 के पिता कयामुद्दीन पुत्र इमामुद्दीन मुसलमान काजी निवासी बारां के खातेदारी में दर्ज कर दी है, जो भू राजस्व अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानों के विपरित तथा अवैधानिक है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी.बी.रिट संख्या 1536/2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटनों को विधि विरुद्ध मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये गये है।

उक्त आवंटन/नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा-16 के तहत अवैधानिक है तथा डी०बी० सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवरुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 02.08.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत गै०मु० तलाई दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त आवंटन/नियमन को शून्य घोषित कर भूमि पूर्ववत गै०मु० तलाई राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

2- प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को जर्ज सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 की ओर से जर्ज अभिभाषक जवाब इस आशय का पेश हुआ कि ग्राम मांगरोल की आराजी साबिक खसरा नं. 701 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा सम्वत् 2034-37 में किस्म माल-2 दर्ज थी। उक्त आराजी कृषि भूमि होने से अप्रार्थी के पिता कयामुद्दीन को कीमतन आवंटित हुई थी। आवंटित भूमि कीमत जमा करने के उपरान्त जर्ज नामातकरण अप्रार्थीगण के पिता को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये। उक्त आराजी के समीप नहर निकल जाने से सेटलमेन्ट 2044 से 2063 की कार्यवाही में किस्म माल-2 को किस्म नहरी-1 में दर्ज किया। साबिक खसरा नं. 701 की आराजी कभी भी तलाई नहीं रही। बल्कि कृषि काश्त योग्य भूमि थी। साबिक खसरा नंबर 701 के नये खसरा नं. 645 रकबा 0.45 है। किस्म नहरी-1 कायम किये जो विधि प्रक्रिया अनुरूप एवं मौजूदा स्थिति अनुरूप दर्ज किये है। अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार जनहित याचिका के निर्णय दिनांक 02.09.2004 में पारित दिशा निर्देशों से असंगत होने से अस्वीकार है। खसरा नंबर 645 रकबा 0.44 है। किस्म नहरी आराजी अप्रार्थी पिता कयामुद्दीन को विधिवत आवंटित हुई, आवंटन उपरान्त आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण के पिता कयामुद्दीन एवं उनके बाद अप्रार्थीगण आराजी को काश्त कर अपने परिवार का जीवन निर्वाह कर रहे हैं। पृथ्वी पर भौगोलिक परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। प्रकृति परिवर्तनशील है। आदिकाल से थल व जल की भौगोलिक स्थितियां सदैव परिवर्तनीय रही है। वर्तमान खसरा नंबर 645 के साबिक खसरा नंबर 701 की भूमि की किस्म के परिवर्तन हुये राजस्व रिकॉर्ड एवं उक्त आराजियात की तत्समय की मौजूदा स्थिति एवं भू उपयोग की पूर्ण जांच पडताल किये बिना ही पुराने रिकॉर्ड के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो निरस्तनीय है। अतः उक्त कार्यवाही ड्रॉप फरमायी जावे। अभिभाषक अप्रार्थी क्रम 2 एवं अप्रार्थी क्रम 2 निरन्तर बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे तथा उनकी ओर से जवाब भी पेश नहीं किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 की ओर से जवाब पेश होने पर प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया।

3- बहस के दौरान परोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम मांगरोल की आराजी खसरा नंबर 645 रकबा 0.45 है., किस्म किस्म नहरी 1 मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2069-72 अप्रार्थी क्रम 1 का हिस्सा 1/7 व अप्रार्थी क्रम 2 का हिस्सा 6/7 के खाते दर्ज है। उक्त आराजी हाल खसरा नंबर 645 रकबा 0.45 है. के मुताबिक मिलान क्षेत्रफल संवत् 2044-63 ग्राम मांगरोल की आराजी साबिक खसरा नंबर 701 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा से कायम हुए हैं। साबिक खसरा नंबर 701 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा की मुताबिक सेटलमेन्ट जमाबन्दी सम्वत् 2014-23 किस्म गै0मु0 तलाई दर्ज रिकार्ड है। बन्दोबस्त संवत् 2044-63 में ग्राम मांगरोल की उक्त आराजी खसरा नंबर 645 रकबा 0.45 है., नहरी 1 कायम किये जाकर अवैधानिक रूप से अप्रार्थी क्रम 1 के पिता कयामुद्दीन पुत्र इमामुद्दीन मुसलमान काजी निवासी बारां के खातेदारी में दर्ज कर दी है, जो भू. राजस्व अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानों के विपरित तथा अवैधानिक है। उक्त आवंटन/नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा-16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त आवंटन/नियमन को शून्य घोषित कर भूमि पूर्ववत गै0मु0 तलाई राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

4- अभिभाषक अप्रार्थी क्रम 1 ने परोकार सरकार के उक्त कथन का खण्डन करते हुए कथन किया कि विवादित आराजी वर्तमान में काश्त योग्य भूमि है जिसके आस पास भी काश्त योग्य



जिला कलेक्टर
बारां (राज.)

भूमि स्थित है। मौके पर कोई तलाई नहीं है। उक्त आराजी अप्रार्थी के पिता को विधिवत आवंटन हुई है। आराजी अप्रार्थी के पिता एवं अप्रार्थी के खाते दर्ज होने के लगभग 30 वर्ष से अधिक समय पश्चात तहसीलदार मांगरोल द्वारा उक्त रेफरेन्स पेश किया गया है जो चलने योग्य नहीं है। अतः रेफरेन्स खारिज फरमाया जावे।

5- हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि ग्राम मांगरोल की जमाबंदी सम्वत् 2069-72 के अनुसार आराजी खसरा नंबर 645 रकबा 0.45 है., किस्म किस्म नहरी 1 अप्रार्थी क्रम 1 के हिस्से 1/7 व अप्रार्थी क्रम 2 के हिस्से 6/7 से खाते दर्ज है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल संवत् 2044-63 ग्राम मांगरोल की उक्त आराजी के हाल खसरा नंबर 645 रकबा 0.45 है. साबिक खसरा नंबर 701 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा से कायम हुए हैं। साबिक खसरा नंबर 701 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा मुताबिक सेटलमेन्ट जमाबन्दी सम्वत् 2014-23 किस्म गै0मु0 तलाई दर्ज रिकार्ड है। बन्दोबस्त संवत् 2044-63 में ग्राम मांगरोल की उक्त आराजी के हाल खसरा नंबर 645 रकबा 0.45 है., नहरी 1 कायम किये जाकर अवैधानिक रूप से अप्रार्थी के पिता कयामुद्दीन पुत्र इमामुद्दीन मुसलमान काजी निवासी बारां के खातेदारी में दर्ज कर दी है, जो भू राजस्व अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानों के विपरित तथा अवैधानिक है। इस प्रकार जिस वक्त भूमि आवंटित/नियमन की गयी थी उस वक्त विवादित आराजी किस्म गै0मु0 तलाई खाता सरकार दर्ज थी, जो आवंटन/नियमन योग्य भूमि नहीं थी। अप्रार्थी क्रम 1 के पिता को उक्त आराजी का आवंटन/नियमन नियम विरुद्ध हुआ है। तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में प्रारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये हम उक्त आवंटन/नियमन को विधि विरुद्ध मानते हुए, आवंटन/नियमन निरस्त करने के लिये रेफरेन्स माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

6- परिणामस्वरूप, प्रार्थी जयें तहसीलदार, मांगरोल का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के वर्तमान में वाके ग्राम मांगरोल में खातेदारी में दर्ज आराजी खसरा नंबर 645 रकबा 0.45 है. किस्म नहरी-1 को जो मूल रूप से सेटलमेन्ट पूर्व साबिक खसरा नंबर 701 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा किस्म गै0मु0 तलाई से बना है जिसका अप्रार्थी के पिता कयामुद्दीन पुत्र इमामुद्दीन मुसलमान काजी निवासी बारां को गलत रूप से आवंटन/नियमन हुआ है, आवंटन/नियमन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेन्स प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

7- तहसीलदार, मांगरोल को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटित आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेन्स होने का नोट लाल स्याही से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें।

आदेश आज दिनांक 28.10.2022 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलेक्टर, बारां
बारां (राज०)